कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

1. प्रस्तावना

हडको ने 1970 में अपनी स्थापना के बाद से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वाले समूहों को किफायती आवास प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी बुनियादी बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने पर अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया है। समग्र रूप से समाज में इसके योगदान के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण, हडको की गतिविधियों को लगातार उन गतिविधियों द्वारा निर्देशित किया गया है जो सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता पर केंद्रित हैं। हालांकि हडको कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप औपचारिक संरचित सीएसआर नीति और जोर देने वाले क्षेत्रों की दिशा में विभिन्न सीएसआर और स्थिरता गतिविधियां कर रहा है, हडको ने सीएसआर नीति तैयार की है और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत विशेष रूप से गतिविधियों को करने के लिए अपने शुद्ध लाभ का एक हिस्सा निर्धारित किया है। इस विशेष बजट से सीएसआर के तहत गतिविधियों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनिवार्य प्राथमिकता/जोर क्षेत्रों से जोड़ा जाता है और हडको की विधिवत अनुमोदित सीएसआर नीति द्वारा विनियमित किया जाता है।

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में कुछ संशोधन किए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धाराओं (1) और (2) के संदर्भ में इन नियमों को कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 कहा जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 दिनांक 25.08.2021 के माध्यम से सीएसआर और डीपीई के संबंध में ""अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न"" (एफएक्यू) सहित कुछ स्पष्टीकरण जारी किए हैं। पत्र दिनांक 21.02.2022 ने सीपीएसई को इन्हें अपनाने के लिए कहा है।" तदनुसार, नए नियमों के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए, हडको की सीएसआर नीति का विवरण नीचे दिया गया है।

सीएसआर नीति

“हडको की सीएसआर नीति" का अर्थ है हडको के सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और निर्देश से युक्त एक विवरण, और इसमें गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं।"

3.उद्देश्य और दृष्टि

हडको की सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य निगम की अपने हितधारकों के परामर्श से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से काम करने की निरंतर प्रतिबद्धता होगी ताकि समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, समुदायों के सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, निवास क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके पिछड़े क्षेत्रों के विकास और गरीबों के लाभ के लिए समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके।

4.सीएसआर जोर क्षेत्र

सीएसआर गतिविधियों के तहत, हडको कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों का अनुपालन करने वाली गतिविधियां करेगा। विभिन्न गतिविधियों और निगरानी आदि पर किए जाने वाले व्यय की राशि। बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदित किया जाएगा। उद्देश्य और दृष्टि के अनुसार, हडको के पास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी संशोधन/अधिसूचना के अनुरूप निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियां/महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे। भारत में समय-समय पर: -

(i) भोजन, आंगनवाड़ी आदि की आपूर्ति के लिए मध्याह्न भोजन, केंद्रीकृत रसोई / रसोई जैसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करके भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, विकलांग सहायकों/उपकरणों और टूलकिट के प्रावधान के लिए परियोजनाओं जैसे प्रस्तावों का समर्थन करके निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपयोगिताएं। एम्बुलेंस, स्वास्थ्य उपकरण आदि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य क्लीनिकों आदि के लिए समर्थन। और स्वच्छता बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित परियोजनाओं को सहायता प्रदान करके। शौचालय/समुदाय/भुगतान और शौचालय आदि का उपयोग करना। जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल आदि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान शामिल है।

(ii) विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना जैसे कक्षा कक्षों का निर्माण/शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लास रूम, बहुउद्देशीय हॉल और अन्य परियोजनाओं के लिए सहायता आदि। और कौशल और आजीविका विकास के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कियोस्क/विक्रेता बाजारों की स्थापना, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक विकास केंद्र आदि के लिए समर्थन। समाज के गरीब और सीमांत वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करना

(iii) लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वृद्धाश्रम स्थापित करना, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं, गरीब/बेघर के लिए रात्रिकालीन आश्रय और बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, आश्रय, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आजीविका आदि प्रदान करने के लिए अन्य उपाय। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक आदि, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए।

(iv) पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। उदाहरण के प्रस्तावों को समर्थन देकर पानी, अपशिष्ट या ऊर्जा प्रबंधन। जल निकायों का संरक्षण, जल पुनर्चक्रण, जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना जैसे सौर प्रकाश, पवन ऊर्जा आदि, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना।

(v) ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों की बहाली और कला के कार्यों सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास। पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प के संवर्धन और विकास के लिए प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण सहित संस्कृति को बढ़ाने के लिए और स्मारकों / विश्व विरासत स्थलों / विरासत स्थलों / तीर्थ स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं / सुविधाओं के प्रावधान के लिए सहायक परियोजनाएं;

(vi) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के दिग्गजों और विधवा सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;

(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालिम्पिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण। बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, खेल विकास केंद्र, व्यायामशाला, स्टेडियम आदि के निर्माण के लिए सहायक परियोजनाएं।

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में योगदान। अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए,

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा वित्तपोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में अंशदान; और

(बी) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में योगदान; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और स्वायत्त निकाय; जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); औषध विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् डेफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

(आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।

(x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं जैसे सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक शौचालय, पेयजल आपूर्ति, लाइटिंग, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना और क्लास रूम, स्मार्ट क्लास रूम आदि की स्थापना के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल के प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का समर्थन करना और गरीबों के लाभ के लिए कियोस्क, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, विक्रेता बाजार की स्थापना सहित आजीविका विकास परियोजनाएं। और ग्रामीण भारत के विकास के लिए बनी कोई भी परियोजना इसके तहत कवर की जाएगी

"(xi) स्लम एरिया डेवलपमेंट (""स्लम एरिया"" का अर्थ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी कानून के तहत घोषित किसी भी क्षेत्र से होगा)।" कम आय वाले आवासों, स्वच्छता/बुनियादी ढांचे आदि में पर्यावरणीय सुधार सहित मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के लिए परियोजनाओं को समर्थन,

आपदा प्रभावित पीड़ितों को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों जैसे आश्रय निर्माण और खाद्य और राहत सामग्री जैसी बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने सहित आपदा प्रबंधन।

ऊपर बताए अनुसार इन विशिष्ट गतिविधियों के अलावा, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप पहचाने गए विभिन्न अन्य गतिविधियों/परियोजनाओं/जोर क्षेत्रों और डीपीई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भी लिया जा सकता है। , ताकि सीएसआर नीति के उद्देश्यों का एक व्यापक/उदार कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

5.कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

""""सीएसआर समिति"" का अर्थ बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति है और इसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा या समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा गठित किया जाएगा।" कंपनी सचिव उपरोक्त समिति के सचिव होंगे।

सीएसआर समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होंगी जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में उल्लिखित है, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित है। सीएसआर समिति बोर्ड को सीएसआर नीति तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी और इसमें कोई भी संशोधन, सीएसआर के तहत किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करेगी और एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी जिसमें सीएसआर परियोजनाओं या अनुमोदित

कार्यक्रमों की सूची, निष्पादन का तरीका, निधियों के उपयोग के तौर-तरीके और कार्यान्वयन अनुसूची, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र और ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों की आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन का विवरण शामिल होगा।

हालांकि, बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, इस आशय के उचित औचित्य या भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर इस तरह की योजना को बदल सकता है।

निदेशक मंडल

सीएसआर प्रावधानों के संबंध में निदेशक मंडल की जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

(ए) सीएसआर नीति को अनुमोदित करें;

(बी) ऐसी नीति की सामग्री को अपनी रिपोर्ट में प्रकट करें और इसे कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी रखें;

(सी) सुनिश्चित करें कि सीएसआर नीति में शामिल गतिविधियां कंपनी द्वारा की जाती हैं;

(डी) यह सुनिश्चित करें कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करती है;

(ङ) संवितरित सीएसआर निधियों के उपयोग के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करें; तथा

(च) यदि कंपनी कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ओ) के तहत की गई अपनी रिपोर्ट में, खर्च नहीं करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा। अधिनियम की धारा 135 (5) और 135 (6) के प्रावधानों के अनुसार राशि और अव्ययित सीएसआर राशि का हस्तांतरण।

(छ) परियोजनाएं/प्रस्ताव जिन्हें शुरू में बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार निर्धारित परियोजना अवधि के दौरान असाधारण परिस्थितियों में, आंशिक रूप से या पूरी तरह से चल रही परियोजना को छोड़ या संशोधित कर सकता है, और इस आशय का उचित औचित्य प्रदान कर सकता है।

7.सीएसआर कार्यान्वयन – परिचालन ढांचा

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

I. सीएसआर गतिविधियां हडको द्वारा या तो स्वयं या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के संशोधित नियम 4(i) के तहत आने वाली किसी भी इकाई के माध्यम से की जाएंगी: -

क) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे धारा 10 के खंड (23 सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (via) के तहत छूट दी गई है या धारा के तहत पंजीकृत है 12ए और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के 80 जी के तहत अनुमोदित, कंपनी द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ, या

बी) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी; या

ग) संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी वैधानिक निकाय। केंद्रीय बोर्ड, राज्य शहरी स्थानीय निकाय, नगर परिषद/निगम, जिला परिषद, आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरण, पंचायत आदि। अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों को करने के लिए; या

घ) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे धारा 10 के खंड (23 सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (via) के तहत छूट दी गई है या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए के तहत पंजीकृत है और 80 जी के तहत अनुमोदित है, और समान गतिविधियों को करने में कम से कम तीन साल का एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा, इन संस्थाओं के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश/आवश्यकताएं (गैर-सरकारी)। ऐसी संस्थाओं द्वारा अनुपालन किया जाना है (जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा इसकी 546वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है) और एमसीए, भारत सरकार द्वारा जारी सीएसआर नीति संशोधन नियम, 2021 के अनुसार अद्यतन किया गया है, अनुलग्नक 'ए' के रूप में इसके साथ संलग्न हैं।

ii. सीएसआर गतिविधियों को करने वाली प्रत्येक संस्था, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म CSR-1 दाखिल करके कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय 21 (MCA 21) पोर्टल में खुद को पंजीकृत करेगा, w.e.f. 01 अप्रैल 2021 को इसे सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए हडको से सीएसआर सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए और हडको को विशिष्ट सीएसआर पंजीकरण संख्या की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

इसके अलावा, यह प्रावधान (एमसीए पोर्टल पर विशिष्ट सीएसआर पंजीकरण संख्या) 01 अप्रैल, 2021 से पहले अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को प्रभावित नहीं करेगा।

iii. "हालांकि, कंपनी अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि कंपनी को सीएसआर गतिविधियों के चयन में 'स्थानीय क्षेत्र' को प्राथमिकता देनी चाहिए, (यह केवल निर्देशिका है और एमसीए अक्सर 25.08.2021 के अनुसार प्रकृति में अनिवार्य नहीं है), लेकिन डीपीई दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जो अन्य बातों के साथ-साथ ""सीपीएसई, जो अपने व्यवसाय की प्रकृति से वाणिज्यिक संचालन का कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, देश के भीतर अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू कर सकता है"", हडको देश के भीतर अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू कर सकता है, क्योंकि इसके संचालन पूरे देश में बिखरे हुए हैं और देश के सभी प्रमुख राज्यों में इसके कार्यालय स्थित हैं।"

iv. सीएसआर गतिविधियों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की भागीदारी से लागू किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों की पहचान/कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल बिंदु होंगे।

v. सीएसआर परियोजनाओं पर पात्र एजेंसियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसमें सीएसआर सहायता रु. एकल परियोजना शुरू करने के लिए 250 लाख। प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए, परियोजना लागत के 100% तक सीएसआर सहायता प्रदान की जा सकती है।

vi. सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त किए जाएंगे। प्रस्तावों की जांच क्षेत्रीय कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रचलित प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। जांच के बाद, व्यवहार्य पाए गए प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश के लिए बोर्ड की सीएसआर समिति के समक्ष रखा जाएगा।

vii. सीएसआर गतिविधियां अनुमोदित वार्षिक योजना/महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्दिष्ट क्षेत्रों में की जाएंगी और उन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात चल रही परियोजनाएं और चल रही परियोजनाओं के अलावा

(ए) चल रही परियोजना को कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 2(1) के तहत परिभाषित किया गया है: -

ए। एक बहु-वर्षीय परियोजना, जो एक से अधिक वित्तीय वर्ष तक फैली हुई है;

बी। शुरू होने के वर्ष को छोड़कर तीन साल से अधिक की समय सीमा नहीं है;

सी। ऐसी परियोजना शामिल है जिसे शुरू में बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन जिसकी अवधि उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से अधिक बढ़ा दी गई है।

"परियोजना को वित्तीय वर्ष के भीतर ""चालू"" के रूप में शुरू किया जाना चाहिए था।" आशय एक ऐसी परियोजना को शामिल करना है जिसमें एक पहचान योग्य शुरुआत और पूरा होने की तारीखें हैं।

"एक चालू परियोजना ""प्रारंभ"" होगी जब एजेंसी ने या तो परियोजना से संबंधित कार्य आदेश जारी किया है या परियोजना के निष्पादन के लिए अनुबंध से सम्मानित किया है।"

चल रही परियोजना की परिभाषा के अनुसार, जिस वित्तीय वर्ष में इसे शुरू किया गया है, उसे छोड़कर अधिकतम अनुमेय समय अवधि तीन वित्तीय वर्ष होगी। किसी भी परिस्थिति में चल रही परियोजना की समयावधि उसकी अनुमेय सीमा से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

ऐसी चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी अनुमोदित समयसीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में की जाएगी और समग्र अनुमेय समय अवधि के भीतर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, करने के लिए की जाएगी।

(बी) चल रही परियोजना के अलावा अन्य का अर्थ है: एक परियोजना जो ऊपर परिभाषित के अनुसार चल रही नहीं है।

viii. हडको परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ इस तरह से सहयोग कर सकता है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

ix. बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर प्रस्तावों के अनुमोदन के बाद, अनुमोदित प्रस्तावों के लिए स्वीकृति पत्र सह समझौते का मुद्दा क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) में किया जाएगा और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सीएसआर फंड जारी किया जाएगा। शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाएगा।

सीएसआर सहायता के 15% से 25% की सीमा में सीएसआर गतिविधि/प्रस्ताव के लिए स्वीकृत राशि की पहली किस्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी की जानी चाहिए और एक वर्ष में किसी भी एक परियोजना को जारी करना 40% से अधिक नहीं होगा। चालू वर्ष का वार्षिक सीएसआर बजट। हालांकि, पहली किस्त के रूप में सीएसआर सहायता के 25% से अधिक जारी करना, रुपये से अधिक जारी करना। शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा 50 लाख और अंतिम किस्त पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा।

xi. कार्यान्वयन एजेंसी को आगे / मध्यवर्ती रिलीज एजेंसी के मुख्य कार्यकारी द्वारा जारी संतोषजनक उपयोग प्रमाण पत्र पर आधारित होंगे और एजेंसी के लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा या एक अभ्यास चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रतिहस्ताक्षरित होंगे।

8.सीएसआर बजट और सीएसआर व्यय का आवंटन

"मैं। हडको द्वारा कंपनी के शुद्ध लाभ के एक हिस्से में से सीएसआर गतिविधियां की जाएंगी, जैसा कि हर साल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि ""बोर्ड ऑफ हर कंपनी...।""" "यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसरण में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करती है।"""

ii. किसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों का वितरण केवल खर्च की राशि नहीं होगी जब तक कि कार्यान्वयन एजेंसी पूरी राशि का उपयोग नहीं करती है और परियोजना के लिए जारी राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करती है।

iii. यदि कंपनी बोर्ड द्वारा निर्धारित सीएसआर राशि (सीएसआर बजट) खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में खर्च नहीं की गई राशि के कारण को निर्दिष्ट करेगा और जब तक अव्ययित राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित नहीं है, ऐसी अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर देगा।

iv. "हडको द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसरण में की गई ऐसी शर्तों को पूरा करने वाली किसी भी चल रही परियोजना के अनुसार अव्ययित शेष राशि, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित की जाएगी। हडको का ""अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व खाता"", और ऐसी राशि कंपनी द्वारा इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के प्रति अपने दायित्व के अनुसरण में खर्च की जाएगी, ऐसा न करने पर, हडको तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर देगा।"

v.सीएसआर के प्रशासनिक ओवरहेड्स वित्तीय वर्ष के लिए हडको के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत (5%) से अधिक नहीं होंगे। प्रशासनिक ओवरहेड्स सीएसआर कार्यों के सामान्य प्रबंधन और प्रशासन के लिए हडको द्वारा

किए गए खर्च हैं। हालांकि, किसी विशेष सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे किए गए खर्चों को प्रशासनिक ओवरहेड्स में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सीएसआर गतिविधियों के प्रबंधन पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए खर्च प्रशासनिक ओवरहेड्स के बराबर नहीं होंगे।

vi. सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा और इसका उपयोग केवल सीएसआर उद्देश्यों के लिए किया जाएगा या इसे हडको के अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया जाएगा और सीएसआर नीति और कंपनी की वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा या इस तरह की अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

vii. सीएसआर राशि हडको द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की जा सकती है, जो कि -

(ए) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, जिसमें नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत धर्मार्थ वस्तु और सीएसआर पंजीकरण संख्या है; या

(बी) उक्त सीएसआर परियोजना के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूहों, समूहों, संस्थाओं के रूप में, या

(सी) एक सार्वजनिक प्राधिकरण:

"""बशर्ते कि कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के प्रारंभ होने से पहले कंपनी द्वारा बनाई गई कोई भी पूंजीगत संपत्ति, इस तरह के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर होगी। इस नियम की आवश्यकता, जिसे उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड के अनुमोदन से नब्बे दिनों से अधिक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है""।" स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क जैसे पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित खर्च, इस तरह के हस्तांतरण के वर्ष में स्वीकार्य सीएसआर व्यय के रूप में योग्य होंगे।

viii. जहां हडको धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत प्रदान की गई आवश्यकता के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित निधि से अधिक राशि खर्च करता है, ऐसी अतिरिक्त राशि को धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत खर्च करने की आवश्यकता के खिलाफ सेट किया जा सकता है। तुरंत तीन वित्तीय वर्षों को सफल करने के लिए शर्तों के अधीन कि :-

(i) सेट ऑफ के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में ऊपर पैरा (2) के अनुसरण में सीएसआर गतिविधियों, यदि कोई हो, से उत्पन्न अधिशेष शामिल नहीं होगा।

(ii) इस आशय का एक संकल्प हडको के बोर्ड द्वारा पारित किया जाता है।

यदि कोई अतिरिक्त राशि सेट ऑफ के लिए छोड़ दी जाती है, तो यह तीसरे वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगी।

ix. सीएसआर व्यय अधिनियम की उक्त अनुसूची VII में प्रविष्टियों से परे गतिविधियों पर खर्च नहीं किया जा सकता है, किसी भी इकाई के कोष में योगदान स्वीकार्य सीएसआर व्यय नहीं है। इसके अलावा, सीएसआर राशि की व्याख्या सरकारी योजनाओं में संसाधन अंतराल के वित्तपोषण के स्रोत के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

9. निगरानी और मूल्यांकन

i) सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी की जाएगी और प्रासंगिक रिपोर्ट हर तिमाही में कॉर्पोरेट कार्यालय को भेजी जाएगी। यदि गतिविधियों के कार्यान्वयन के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कोई प्रतिकूल बिंदु देखा जाता है, तो इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रधान कार्यालय को दी जाएगी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भुगतान जारी करने से पहले प्रगति को प्रमाणित करेगा और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करके परियोजना की निगरानी करेगा और साइट का दौरा, परियोजना की तस्वीरें और सीएसआर फंड का उपयोग प्रमाण पत्र / हडको द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करेगा।

ii)जारी की गई किस्त का उपयोग रिलीज की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा और यदि इसका उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो एजेंसी उसी और संभावित अवधि के कारणों के साथ हडको को सूचित करेगी। जिसके दौरान एजेंसी द्वारा उपयोग किया जाएगा। इसके विश्लेषण के आधार पर हडको एक निर्णय लेगा जो एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

iii) परियोजना घटकों में परिवर्तन, परियोजना लागत में परिवर्तन और साइट/स्थान में परिवर्तन, फंड के उपयोग के लिए समय के विस्तार सहित समय का विस्तार आदि सहित परियोजना में कोई बाद का संशोधन/संशोधन। और परियोजना को पूरा करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

iv) सीएसआर समिति और बोर्ड को हर छह महीने में सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

10.प्रभाव मूल्यांकन

i) एचयूडीसीओ रुपये के परिव्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं के बोर्ड द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन करेगा। 1 करोड़ या उससे अधिक, और जो प्रभाव अध्ययन करने से पहले कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया गया है।

ii)उपरोक्त प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किया जाएगा। इस संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तक पहुंचने और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश प्रदान करने के लिए वेब-लिंक को उक्त नियम का पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा।

iii) जहां भी लागू हो, कंपनी सीएसआर गतिविधियों पर प्रभाव मूल्यांकन करने के मामले में, कंपनी उस वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए व्यय बुक करेगी, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर खर्च का 2% या रुपये होगा। 50 लाख, इनमें से जो भी अधिक हो।

11. सीएसआर रिपोर्टिंग

किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी जिसमें समय-समय पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे।

12. सीएसआर गतिविधियों का अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शन

हडको अनिवार्य रूप से अपनी सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सार्वजनिक पहुंच के लिए कंपनी की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संरचना का खुलासा करेगा।

13. सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव और रखरखाव

सीएसआर परियोजनाओं के ओ एंड एम के लिए किसी सीएसआर अनुदान पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, सीएसआर गतिविधियों के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए, आवेदक एजेंसी से लिखित आश्वासन प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक डीपीआर अनिवार्य रूप से संचालन और रखरखाव प्रबंधन का विवरण बहुत स्पष्ट रूप से देगा और कार्यान्वयन के लिए धन जारी करने से पहले इस प्रकार चयनित एजेंसी से एक उपक्रम की आवश्यकता होगी।

14. विविध

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में निर्धारित अपने वैधानिक दायित्व के अनुसरण में कंपनी द्वारा इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई गतिविधियों से है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

ए। कंपनी के सामान्य व्यवसाय के अनुसरण में की गई गतिविधियां;

ख.अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के अलावा भारत के बाहर किए गए कार्यकलाप;

सी। अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान;

डी। वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) के खंड (के) खंड 2 में परिभाषित कंपनी के कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली गतिविधियां;

इ। अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रायोजन के आधार पर कंपनी द्वारा समर्थित गतिविधियां;

च. भारत में लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी अन्य वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए की गई गतिविधियां।

आम तौर पर, सीएसआर गतिविधि बड़े पैमाने पर जनता को लाभान्वित करना है और गतिविधि लाभार्थियों के किसी भी वर्ग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण होनी चाहिए। सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियाँ जो केवल कंपनी के कर्मचारी और उनके परिवारों को लाभान्वित करती हैं, उन्हें अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियां नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, मैराथन / पुरस्कार / धर्मार्थ योगदान / विज्ञापन / टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजन आदि जैसे एकमुश्त कार्यक्रम। सीएसआर व्यय के हिस्से के रूप में योग्य नहीं होगा।

15. कंपनी अधिनियम के साथ इस नीति के किसी भी संघर्ष के मामले में, कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान प्रबल होंगे।

अनुलग्नक-क

गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश

ए। पात्रता मानदंड

सीएसआर सहायता के प्रस्ताव, मौजूदा सीएसआर नीति में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप, संस्थाओं (एनजीओ - सोसायटी / ट्रस्ट / धारा 8 कंपनी) से प्राप्त और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के प्रस्तावों पर आवेदन के आधार पर विचार किया जाएगा: -

i) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे धारा 10 के खंड (23 सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (via) के तहत छूट दी गई है या धारा 12ए के तहत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 के 80 जी के तहत अनुमोदित है,

ii) सहायता के लिए आवेदन करने की तारीख पर इकाई 5 साल के लिए अस्तित्व में होनी चाहिए (लागू होने वाली पंजीकरण की तारीख से गणना की जानी चाहिए)।

iii) गैर-सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव। इकाई अनुमोदित हडको सीएसआर नीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके संविधान और/या शासी कानून के तहत प्रस्तावित गतिविधि करने और अनुदान आदि प्राप्त करने के लिए इसे अनिवार्य / अनुमति दी जानी चाहिए।

iv)संस्थाओं को पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान तीन समान परियोजनाओं में से कम से कम दो को पूरा करना चाहिए था, जिसका मूल्य प्रस्तुत करने के तहत प्रस्ताव की परियोजना लागत का 50% होना चाहिए। यदि परियोजना की प्रकृति के लिए रखरखाव की आवश्यकता होती है, तो गैर-सरकारी संस्थाओं को भी पूरी की गई परियोजनाओं का रखरखाव रिकॉर्ड प्रस्तुत करना चाहिए।

v) गैर-सरकारी संस्थाओं को पिछले पांच वर्षों में इसके द्वारा किए गए सभी मामलों में कम से कम 60% परियोजनाओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करना चाहिए था। गैर-सरकारी संस्थाओं को अपनी लागत, पूर्णता अवधि, वर्तमान प्रगति और उस एजेंसी के नाम के साथ हाथ में कुल कार्य (सीएसआर और अन्य कार्य) की सूची की घोषणा करनी होती है जिसके साथ काम कर रहा है। इसके अलावा, गैर-सरकारी संस्थाओं को सीएसआर कार्य नहीं सौंपे जाएंगे जो गैर-सरकारी संस्थाओं के पिछले तीन वर्षों में उच्चतम टर्नओवर (वार्षिक खाते से सत्यापित होने के लिए) से दोगुना से अधिक के लिए संचयी कार्य करते हैं। इस खाते में किसी भी गलत घोषणा पर हडको द्वारा उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(उपरोक्त के समर्थन में, गैर-सरकारी संस्थाओं को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में उठाए गए/निष्पादित/पूर्ण/प्रगति में / नहीं लिए गए प्रस्तावों और हाथ में दिए गए प्रस्तावों का विवरण (वर्षवार) प्रस्तुत करना होगा। संदर्भ, सहायक दस्तावेज, फोटोग्राफ, कार्य पत्र पुरस्कार आदि के साथ। "(i)"

vi) गैर-सरकारी संस्थाओं का भारत में एक स्थायी कार्यालय/पता होना चाहिए जिसमें बुनियादी बुनियादी बुनियादी ढांचा सुविधाएं {परिसर (चाहे वह स्वयं का हो या किराए पर), बुनियादी कार्यालय उपकरण, बुनियादी शिक्षण सहायता उपलब्ध आदि) होनी चाहिए} आवेदन में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा इंगित किया जाना है।

vii) गैर-सरकारी संस्थाओं का पूर्ववृत्त सत्यापन योग्य/पुष्टि के अधीन होना चाहिए और इसमें स्थिर बुनियादी ढांचा होना चाहिए। गैर-सरकारी संस्थाओं को स्टाफ संरचना/संख्या, नाम भूमिकाओं और कर्मचारियों/आयोजक की जिम्मेदारियों आदि का विवरण प्रस्तुत करना होगा। परियोजना में शामिल है, संगठन की क्षमता, कार्यक्रम / परियोजना के संदर्भ में स्टाफ अनुभव और विशेषज्ञता, संगठन द्वारा कवर किया गया भौगोलिक क्षेत्र, संगठन द्वारा की गई अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय आवास बैंक / भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए सहायक दस्तावेजों और निर्धारित दस्तावेजों के साथ। इकाई और उसके प्रमोटरों और प्रमुख कर्मियों, जैसा लागू हो।

viii) क्रिसिल, केयर, आईसीआरए और आईआरआर से वैध स्वैच्छिक संगठन ग्रेडिंग (वीओ रेटिंग)। ग्रेडिंग शीर्ष या सर्वोत्तम ग्रेडिंग के नीचे दो पायदान से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात ग्रेडिंग शीर्ष तीन श्रेणियों के भीतर होनी चाहिए। इकाई को प्रस्ताव के कार्यान्वयन के दौरान ग्रेडिंग को वैध बनाए रखने की आवश्यकता होगी और इसमें किसी भी बदलाव के बारे में हडको को सूचित करना आवश्यक होगा।

ix) गैर-सरकारी संस्थाओं के पास प्रस्तावित परियोजना के ओ एंड एम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह होना चाहिए या उचित टाई-अप की पहचान करने और स्थापित करने की आवश्यकता है (पूरा होने के बाद ओ एंड एम की आवश्यकता वाले प्रस्तावों के लिए)।

केंद्र सरकार के साथ काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाएं।, राज्य सरकार। वर्तमान में या पिछले 3 वित्तीय वर्षों में (सक्षम प्राधिकारी से संतोषजनक कार्यान्वयन का संकेत देने वाले प्रासंगिक प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित) और केंद्र सरकार के पैनल में, राज्य सरकार, सीपीएसई को प्राथमिकता दी जा सकती है।

xi) गैर-सरकारी संस्थाओं का सरकार और हडको के निदेशक मंडल के साथ कोई टकराव नहीं होना चाहिए।

गैर-सरकारी संस्थाओं के पास परियोजना के लिए जारी राशि का उपयोग करने के लिए छह महीने हैं, हालांकि यदि राशि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इकाई छह महीने की समाप्ति से पहले हडको को वापस कर देगी (जो कि फिर से जारी किया जा सकता है इकाई को जब यह तैयार है / उसी का उपयोग करने की स्थिति में) ऐसा न करने पर एसबीआई बेस रेट @ दंडात्मक ब्याज रिलीज की तारीख से लगाया जाएगा।

एक वर्ष में सभी गैर सरकारी संगठनों के प्रस्तावों के लिए आवंटन वार्षिक सीएसआर प्रतिबंधों के 25% की समग्र सीमा तक सीमित होगा या समय-समय पर तय किया जाएगा।

एनजीओ के लिए अनुमोदित सीएसआर नीति में वर्णित निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र का भी पालन किया जाएगा।

xv) अन्य सभी पहलू जो इन दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं हैं, पहले से ही अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसार होंगे। इसके अलावा, गैर-सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विचार किया जाएगा:

क) कोई भी गैर-सरकारी संस्थाएं जिनके पास कानूनी विवाद लंबित हैं और या धोखाधड़ी, धन का दुरुपयोग, लाभार्थियों का शोषण आदि जैसे अपराधों के संबंध में पूछताछ। विचार किया जाना है।

ख)गैर सरकारी सीएपीएआरटी, सीएसडब्ल्यूबी, महिला और बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आदि जैसी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाली गई संस्थाएं। अस्वीकृत किया जाना है।

ग) गैर-सरकार। संस्थाओं को समय-समय पर बनाए गए विभिन्न विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, इसके तहत बनाए गए नियम और सरकार या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश।

उपरोक्त के समर्थन में एक स्व-घोषणा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

i) विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र।

ii)रजिस्ट्रार के साथ फॉर्म सीएसआर-1 (ई-फॉर्म पोर्टल) भरने के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ एजेंसी / इकाई पंजीकरण का सबूत देने वाले दस्तावेजों की प्रति। प्रैक्टिस में चार्टर्ड एकाउंटेंट या प्रैक्टिस में कंपनी सचिव या प्रैक्टिस में कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत फॉर्म की एक प्रति एमसीए पोर्टल से उत्पन्न सीएसआर पंजीकरण संख्या के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

iii) दस्तावेज साक्ष्य एजेंसी के निर्माण और उसके प्रकार अर्थात। अधिनियम / एमओए उपनियम / ट्रस्ट डीड आदि का गठन, निगमन / पंजीकरण का प्रमाण पत्र और परियोजना को लागू करने और भूमि के कब्जे के लिए भूमि पर

एजेंसी के स्वामित्व या व्यवस्था / अधिकारों का सबूत देने वाले दस्तावेज, जिसके बाद प्रस्तावित गतिविधि की जानी है आदि। (पंजीकरण प्रमाण पत्र / ट्रस्ट डीड / एमओए / एमओयू की प्रति)।

iv) प्रस्तावित परियोजना को लेने और प्रस्तावित गतिविधि के लिए हडको से वित्तीय सहायता प्राप्त करने और आवश्यक दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिए भी संकल्प/आदेश (जैसा लागू हो)। अपने प्रमोटरों आदि को अधिकृत करके। जहां भी आवश्यक हो, सामान्य मुहर लगाना सहित।

v) एजेंसी और उसके प्रमोटरों और प्रमुख कर्मियों के संबंध में एनएचबी/आरबीआई के केवाईसी मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों को जमा करना।

vi) प्राप्त अनुदान आदि का विवरण और पिछले 5 वर्षों में की गई परियोजनाओं और जनशक्ति की उपलब्धता का विवरण।

vii) पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (लेखा परीक्षित)।

viii) पैन कार्ड की प्रति और टैन नंबर

ix) निदेशक मंडल/न्यासी/कार्यकारी समिति के सदस्यों/शासी निकाय के सदस्यों की सूची, उनके पते और संपर्क नंबर।

x) इस आशय का प्रमाण पत्र कि संस्थाओं को किया गया योगदान आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 12ए के साथ-साथ 80जी के साथ-साथ मौजूदा / लागू वित्त विधेयक के संबंधित खंडों के लिए कर छूट के लिए योग्य है, वैध छूट प्रमाण पत्र की प्रति के साथ केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी संस्था को छोड़कर।

i) घोषणा कि क्या निदेशक मंडल/न्यासी/कार्यकारी समिति के सदस्यों/शासी निकाय के सदस्यों में से किसी के पास हडको से निपटने वाला कोई अधिकारी है या हडको के किसी बोर्ड के सदस्य से संबंधित है।